

Regarding demand for regularization of contractual workers

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा-कर्मियों की समस्याओं को सदन के बीच रखना चाहता हूं। संविदा-कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी व नियमित लाभ न मिलने से ये लोग समाज में परेशान, उपेक्षित और निरीह हैं। आशा बहुओं को केवल दो हजार रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8850 रुपए, शिक्षा-मित्रों को केवल दस हजार, आंगनबाड़ी कर्मियों को केवल पांच हजार, सहायकों को केवल 2700, अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत सहायकों को केवल पांच हजार और रसोईयों को केवल दो हजार मिल रहे हैं। यह उनका मानदेय है। इस मानदेय के साथ उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है, उसमें बुरी तरह से शोषण हो रहा है।

सभापति जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। देश के अंदर ये लोग सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हुए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है। मेरी सीधी मांग है कि केन्द्र सरकार, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं और सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा है, वह उन्हें दिया जाए। (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, मैं आपको मौका दूंगा। आप 30 सेकेंड में अपना डिमांड रखें।

श्री धर्मेन्द्र यादव : एक महीने में आप उनसे एसआईआर करवायेंगे और उन्हें कोई सुविधा नहीं देंगे। यह बर्दाश्त नहीं हो पायेगा। उनको स्थायी कीजिए, उनकी जो सेवा-शर्तें हैं, वह उन्हें दी जानी चाहिए।